भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3375

जिसका उत्तर शुक्रवार, 05 अगस्त, 2022 को दिया जाना है

मध्य प्रदेश में ग्राम न्यायालय

+3375. श्री गजेन्द्र उमराव सिंह पटेल :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां ग्राम न्यायालय और न्याय पंचायत कार्यरत हैं ;

(ख) मध्य प्रदेश के जनजातीय और पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसी न्याय पंचायतों का जिला -वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इन ग्राम न्यायालयों में किस प्रकार के मामलों की सुनवाई हो रही है ;

(घ) क्या सरकार का इन ग्राम न्यायालयों के क्षेत्राधिकार को व्यापक बनाने का प्रस्ताव है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने इन ग्राम न्यायालयों और न्याय पंचायतों की सफलता दर का विश्लेषण किया है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ग) : नागरिकों को उनके द्वार तक न्याय की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए केन्द्रीय सरकार ने ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 अधिनियमित किया है । ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 की धारा 3(1) के निबंधनों में, राज्य सरकारें संबंधित उच्च न्यायालयों के परामर्श से ग्राम न्यायालय स्थापित करने के लिए उत्तरदायी है । तथापि, अधिनियम ग्राम न्यायालयों की स्थापना को आज्ञापक नहीं बनाता है । ग्राम न्यायालय अधिनियम किसी ऐसे जिले या किसी राज्य के जहां निकटस्थ पंचायत समूह के किसी समूह के लिए मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत नहीं है, वहां मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत या मध्यवर्ती स्तर पर पंचायत समूह के किसी समूह के लिए ग्राम न्यायालयों

की स्थापना का उपबंध करता है । ग्राम न्यायालय सिविल और दांडिक अधिकारिता के साथ प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रटेट का न्यायालय समझा जाता है जैसा अधिनियम की पहली और दूसरी अनुसूची में उपबंधित है । केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार के पास ऐसी अनुसूचियों में किसी मद को जोड़ने या लोप करने की शक्ति है । मध्य प्रदेश राज्य सरकार/ उच्च न्यायालय द्वारा उपलब्ध कराए गए डाटा के अनुसार स्थानों का नाम जहां ग्राम न्यायालय क्रियाशील है उपाबद्ध है ।

(घ) : वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ड.) और (च) : ग्राम न्यायालय पोर्टल पर अपलोड किए गए डाटा के अनुसार 5,248 मामले (121 सिविल और 5,127 दांडिक मामलें) अप्रैल, 2021 से मार्च 2022 तक मध्य प्रदेश राज्य के इन ग्राम न्यायालयों में निपटाए गए थे ।

****

उपाबंध

लोक सभा अतारांकित प्रश्न सं. 3375 जिसका उत्तर तारीख 05/08/2022 को दिया जाना है, के भाग (क) से (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण

क्र. सं.	जिले का नाम	अवस्थिति
1	अलीराजपुर	जोबट
2	अनूपपुर	कोतमा
3	अशोकनगर	चंदेरी
4	बड़वानी	सेंधवा
5	बैतूल	मुलताई
6	भिंड	लहार
7	भोपाल	बैरसिया
8	छतरपुर	बिजावर
9	छिंदवाड़ा	पांढ़ुरना
10	दमोह	हटा
11	दतिया	सेंधवा
12	देवास	कन्नौद
13	धार	मनावर
14	गुना	चाचौड़ा
15	ग्वालियर	डबरा
16	होशंगाबाद	सोहागपुर
17	जबलपुर	पाटन
18	झाबुआ	थांदला
19	मंदसौर	गरोठ
20	मुरैना	अम्बाह
21	नरसिंहपुर	गाडरवारा
22	नीमच	मनासा
23	पन्ना	पवई
24	रायसेन	बरेली
25	राजगढ़	बायोरा
26	रतलाम	जावर
27	रीवा	सिरमौर
28	सागर	खुरई
29	सतना	नागौद
30	सीहोर	बुधनी
31	सिवनी	लखनादौन
32	शहडोल	जयसिंहनगर
33	शाजापुर	आगर
34	शिवपुरी	करैरा
35	सीधी	मझौली
36	बालाघाट	बालाघाट
37	टीकमगढ़	निवाडी
38	उज्जैन	महिदपुर
39	विदिशा	सिरोंज
40	मंडलेश्वर	भीकनगांव
41	अलीराजपुर	अलीराजपुर
42	अनूपपुर	अनूपपुर
43	अशोकनगर	अशोकनगर
44	बालाघाट	बालाघाट
45	बड़वानी	बड़वानी

46	बैतूल	बैतूल
47	भिंड	भिंड
48	भोपाल	भोपाल
49	बुरहानपुर	बुरहानपुर
50	छतरपुर	छतरपुर
51	छिंदवाड़ा	छिंदवाड़ा
52	दमोह	दमोह
53	दतिया	दतिया
54	देवास	देवास
55	धार	धार
56	डिंडोरी	डिंडोरी
57	खंडवा	खंडवा
58	गुना	गुना
59	ग्वालियर	ग्वालियर
60	हरदा	हरदा
61	होशंगाबाद	होशंगाबाद
62	इंदौर	इंदौर
63	जबलपुर	जबलपुर
64	झाबुआ	झाबुआ
65	कटनी	कटनी
66	मंडला	मंडला
67	मंदसौर	मंदसौर
68	मुरैना	मुरैना
69	नरसिंहपुर	नरसिंहपुर
70	नीमच	नीमच
71	पन्ना	पन्ना
72	रायसेन	रायसेन
73	राजगढ़	राजगढ़
74	रतलाम	रतलाम
75	रीवा	रीवा
76	सागर	सागर
77	सतना	सतना
78	सीहोर	सीहोर
79	सिवनी	सिवनी
80	शहडोल	शहडोल
81	शाजापुर	शाजापुर
82	श्योपुर	श्योपुर
83	शिवपुरी	शिवपुरी
84	सीधी	सीधी
85	टीकमगढ़	टीकमगढ़
86	उज्जैन	उज्जैन
87	उमरिया	उमरिया
88	विदिशा	विदिशा
89	मंडलेश्वर	मंडलेश्वर

****